मुख्य समाचार :–

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनज़र ईंधन आपूर्ति और मुद्रास्फीति पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की।
- केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की।
- प्रदेश में आज रात्रि साढ़े आठ बजे से साढ़े नौ बजे तक 'अर्थ आवर' मनाया जाएगा। इस दौरान सभी गैर–जरूरी लाइटें और विद्युत उपकरण बंद रखने की अपील की गई।
- राज्य में अप्रैल माह से प्री–एसआईआर के तहत सघन मैपिंग अभियान शुरू किया जाएगा।

पश्चिम एशिया संघर्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए ईंधन आपूर्ति और मुद्रास्फीति पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए राज्यों की तैयारी और योजनाओं की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त वैश्विक तनाव के बीच ईंधन की आपूर्ति और महंगाई पर भी विचार–विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार, इस मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

ईंधन

केंद्र सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत के पास वर्तमान में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। यह अगले दो महीनों के लिए आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और एलपीजी तथा पीएनजी की उपलब्धता संतोषजनक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी पूरी या उससे अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं।

संयुक्त सचिव ने कहा कि 4 मार्च से अब तक लगभग 30 हजार टन वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई है। इस दौरान रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, औद्योगिक कैंटीन और प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर भी उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं, देहरादून जिले में गैस आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। जिला पूर्ति अधिकारी के के अग्रवाल ने बताया कि गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग, गोदाम से गैस की सप्लाई, और समय–समय पर निरीक्षण व छापेमारी की कार्रवाई जारी है।

जनमिलन कार्यक्रम

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जनमिलन कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत अल्मोड़ा जिले के इसलना खाड़ी, सुनौली और भैसोड़ी गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और विभिन्न विकास कार्यों के लिए विधायक निधि से कुल 22 लाख रुपये देने की घोषणा की। साथ ही कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया गया।

इसलना खाड़ी में ग्रामीणों ने सड़क कटिंग, देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण, राशन कार्ड में नाम जोड़ने और आर्थिक सहायता की मांग उठाई। इस पर कैबिनेट मंत्री ने सड़क कटिंग के लिए ढाई लाख रुपये और मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 2 लाख रुपये देने की घोषणा की।

सुनौली गांव में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, मोबाइल नेटवर्क और खेती की सुरक्षा के लिए तारबाड़ की मांग रखी। इस दौरान श्रीमती आर्या ने कहा कि सरकार विकास की राजनीति में विश्वास रखती है और दूरस्थ गांवों तक विकास पहुंचाना उसकी प्राथमिकता है। उन्होंने सभी लंबित समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया।

'अर्थ आवर'

उत्तराखण्ड शासन ने आज रात साढ़े आठ बजे से साढ़े नौ बजे तक 'अर्थ आवर' मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान प्रदेशवासियों से एक घंटे के लिए सभी गैर–जरूरी लाइटें और विद्युत उपकरण बंद रखने की अपील की गई है।

यह पहल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने तथा आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। यह अभियान डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया, नई दिल्ली के पत्र के क्रम में संचालित किया जा रहा है।

प्री–एसआईआर

प्रदेश में आगामी अप्रैल माह से एसआईआर का सघन अभियान शुरू होगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों और प्रगति की जानकारी दी।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में प्री–एसआईआर चरण में 85 प्रतिशत से अधिक मैपिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। अप्रैल से डोर–टू–डोर सघन अभियान चलाकर कम मैपिंग वाले बूथों पर विशेष ध्यान देते हुए शेष कार्य पूरा किया जाएगा। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक बूथ पर अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की सूची तैयार की जा रही है, जिससे मतदाता सूची का शुद्धिकरण और प्रभावी ढंग से किया जा सके।

डॉ. जोगदंडे ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए 'बुक ए कॉल विद बीएलओ' फीचर शुरू किया गया है। इसके लिए मतदाता voters.eci.gov.in वेबसाइट या मोबाइल ऐप ECI-NET डाउनलोड करके अपने बीएलओ के साथ कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक होने के बाद दो दिन के भीतर संबंधित बीएलओ मतदाता से संपर्क करेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 11 हजार 733 पोलिंग बूथों के सापेक्ष अब तक विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा 19 हजार 116 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए हैं।

स्वीकृति

प्रदेश सरकार ने कुंभ मेले से पहले हरिद्वार में दो नए पुलों के निर्माण को स्वीकृति दी है। कुंभ मेलाधिकारी सोनिका ने बताया कि दोनों पुलों की अनुमानित लागत लगभग 25 करोड़ रुपये है और इनका निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इन पुलों के निर्माण से मॉनसून के दौरान होने वाले नुकसान से बचाव संभव होगा। साथ ही कुंभ मेले के दौरान यातायात संचालन में भी सुविधा मिलेगी और बड़े स्नान पर्वों के समय जाम की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।

टीवी रेटिंग नीति

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश में टेलीविज़न दर्शकों की रेटिंग में पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए टीवी रेटिंग नीति (टीआरपी) 2026 को अधिसूचित किया। मंत्रालय ने कहा कि यह नीति टीवी रेटिंग सेवाएँ प्रदान करने वाली एजेंसियों के पंजीकरण, संचालन, ऑडिट और निगरानी के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित करती है।

यह नीति दर्शक संख्या में पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाई गई है। अब टीवी रेटिंग एजेंसी के रूप में पंजीकरण कराने की इच्छुक कंपनी के लिए शुद्ध संपत्ति को वर्तमान बीस करोड़ रुपये से घटाकर पाँच करोड़ रुपये कर दिया गया है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निदेशक मंडल में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए जिनका प्रसारकों/विज्ञापनदाताओं/विज्ञापन एजेंसियों से कोई संबंध न हो। नियमों का पालन न करने पर दंड लगाया जाएगा। इसमें रेटिंग के अस्थायी निलंबन और बार–बार उल्लंघन करने पर पंजीकरण रद्द करना शामिल है।

पर्यवेक्षण

शासन ने जिला नियोजन और अनुश्रवण समितियों तथा विकास कार्यों के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में 11 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। राज्यपाल गुरमीत सिंह से स्वीकृति मिलने के बाद प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुन्दरम ने पूर्व में जारी सभी आदेशों को निरस्त करते हुए नई सूची लागू की है।

एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर.....

पेट्रोल– डीजल पर उत्पाद शुल्क पर कटौती की खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने पहले पृष्ठ पर स्थान दिया है। इस खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है– महंगाई थामने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये की कटौती

पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक पर दैनिक जागरण का शीर्षक है– चुनौती से निपटना साझा जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री बोले– स्थिति पर काबू पा लेगी 'टीम इंडिया'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात को हिन्दुस्तान समाचार पत्र ने स–चित्र प्रकाशित किया है। दून और हरिद्वार में रक्षा उत्पादन हब की तैयारी शीर्षक के साथ हिन्दुस्तान लिखता है– मोदी से मुलाकात कर विकास परियोजनाओं पर सहयोग मांगा। दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेस वे तथा टिहरी पम्प्ड स्टोरेज प्लांट के लोकार्पण और पंतनगर एयरपोर्ट के शिलान्यास का न्योता दिया।

मुख्य समाचार एक बार फिर–

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनज़र ईंधन आपूर्ति और मुद्रास्फीति पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की।
- केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की।
- प्रदेश में आज रात्रि साढ़े आठ बजे से साढ़े नौ बजे तक 'अर्थ आवर' मनाया जाएगा। इस दौरान सभी गैर–जरूरी लाइटें और विद्युत उपकरण बंद रखने की अपील की गई।
- राज्य में अप्रैल माह से प्री–एसआईआर के तहत सघन मैपिंग अभियान शुरू किया जाएगा।